NATIONAL BROADCASTING POLICY TO BE A REALITY SOON

Govt has reiterated its commitment of coming up with a National Broadcast Policy and this was confirmed by Neerja Shekar, Additional Secretary (Broadcasting) & CVO, Ministry of Information and Broadcasting in her address at 9th CII BIG Picture Summit.

राष्ट्रीय प्रसारण नीति शीघ्र ही वास्तविकता होगी

सरकार ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति के साथ आने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस बात की पुष्टि नीरजा शंकर, अतिरिक्त सचिव (प्रसारण) और सीवीओ, सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 9 वें सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन में अपने संबोधन में की।

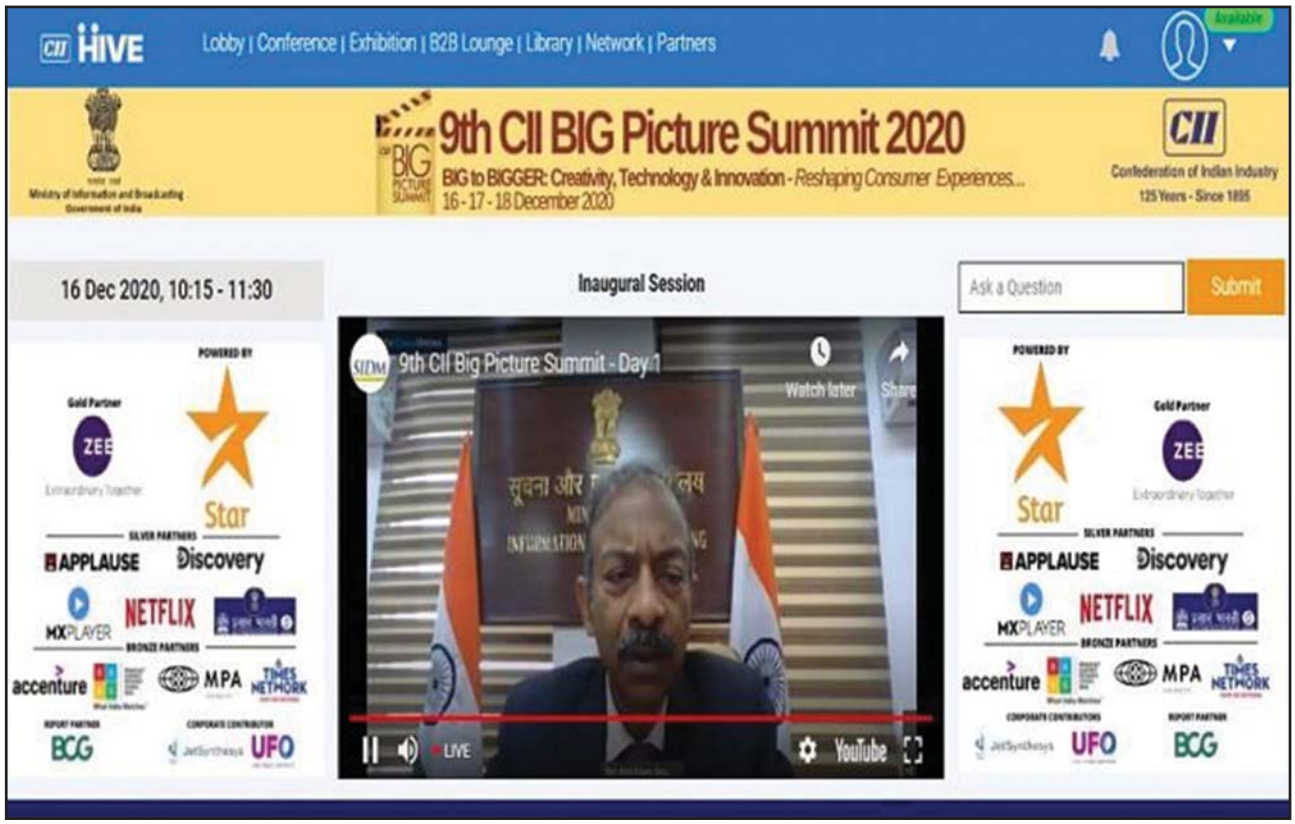

"Though, the consultations on the National Broadcasting Policy were held with the stakeholders and by the industry some time back, we have been putting in various parts together and including the emerging issues as well. I feel that we are getting pretty close to coming up with a draft version," said Neerja Shekar.

नीरजा शंकर ने कहा कि 'हालांकि राष्ट्रीय प्रसारण नीति पर विचार विमर्श हितधारको के साथ आयोजित किया गया था और उद्योग द्वारा कुछ समय पहले हम विभिन्न भागों में एक साथ और उभरते हुए मुद्दों को भी शामिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ड्राफ्ट संस्करण के साथ आने के लिए काफी निकट हैं।'

Media and entertainment are one of the fastest growing sectors in the Indian economy with potential to contribute significantly in India's move towards becoming a $5 trillion economy, Shekar said that all the forms of media are growing simultaneously not necessarily at the cost of the other because the reach of different forms of media can be region specific or platform specific.

NEERJA SHEKAR

Speaking about granting infrastructure status to the broadcast industry, Shekar sought industry support in terms of giving important inputs to the ministry. "We have been trying to support the broadcasting by getting it declared as infrastructure. But we have not been able to succeed because the few times that we went to the finance ministry they were not convinced with our arguments. I would request the broadcasting industry and the OTT platforms to please support us on this because we will need your help in taking this case to the finance ministry and convince them that as the status of infrastructure has been given to the telecommunication sector, we are also a fit area for that. But we will not be able to do it without your support."

S K Gupta, Secretary, Telecom Regulatory Authority of India, said that today India is passing through a digital revolution era. India has got 750 billion broadband subscribers and 550 million smartphone subscribers, their smartphone adoption rate is 30% year on year, meaning there are a large number of people who will have a smartphone and can see TV or other contents on the phone. He said that India is at the stage of adoption of the 5G technology.

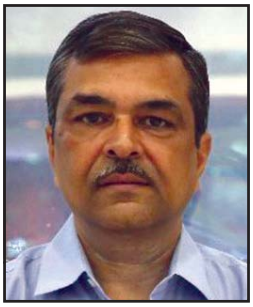

S K GUPTA

K Madhavan, Chairman, CII National Committee on Media & Entertainment and Managing Director, Star India Pvt Limited & Disney India, said: "In my many years in the industry disruption on this scale has never been imagined. However, the entire media and entertainment industry came together to engage and entertain millions of viewers."

K MADHAVAN

Madhavan added that the industry has the potential to grow to $100 billion by 2025. "The pandemic has driven customers to adopt technology. There has been never seen before growth in e-commerce, online video and digital gaming sectors. But to achieve this potential, we need light touch regulations and a much simpler governance structure in place," he said. ■

मीडिया और मनोरंजन भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है जिसमें कि भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मीडिया के सभी रूप एकसाथ बढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि दूसरे की कीमत पर, क्योंकि मीडिया के विभिन्न रूपों की पहुंच क्षेत्र विशिष्ट या प्लेटफार्म विशिष्ट हो सकती है।

प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढ़ांचा का दर्जा देने के बारे में बोलते हुए श्री शेखर ने मंत्रालय को महत्वपूर्ण जानकारी देने के संदर्भ में इस उद्योग का समर्थन मांगा। 'हम इसे बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित करके प्रसारण का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सफल नहीं हो पाये, क्योंकि कुछ समय पहले जब हम वित्त मंत्रालय के सामने गये थे तो वे हमारे तर्कों से सहमत नहीं थे। मैं प्रसारण उद्योग और ओटीटी प्लेटफार्मों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर हमारा समर्थन करें क्योंकि हमें इस मामले को वित्त मंत्रालय तक ले जाने में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि जैसाकि दूरसंचार क्षेत्र को बुनियादी ढ़ांचे का दर्जा दिया गया है, वैसे ही हम भी उनके लिए फिट क्षेत्र हैं। लेकिन हम इसे आपके समर्थन के बिना नहीं कर पायेंगे।'

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव श्री एस के गुप्ता ने कहा कि आज भारत डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। भारत में 750 बिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर और 550 मिलियन स्मार्टफोन सब्सक्राइबर हैं, इनकी स्मार्ट फोन अपनाने की दर साल दर साल 30% है, मतलब बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन होगा और फोन पर टीवी या अन्य सामग्री देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 5 जी तकनीकी को अपनाने के मार्ग पर है।'

सीआईआई नेशनल कमिटी ऑन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के.माधवन और स्टार इंडिया प्रा. लि. व डिज्नी इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कहा कि 'इस पैमाने पर उद्योग में मेरे कई वर्षों के व्यवधान की कभी कल्पना नहीं की गयी थी। हालांकि, पूरे मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने लाखों दर्शकों को शामिल करने और उनका मनोरंजन करने के लिए एकसाथ आये हैं।'

श्री माधवन ने कहा कि उद्योग में 2025 तक 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की क्षमता है। महामारी ने तकनीकी को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन वीडियो और डिजिटल गेमिंग के क्षेत्रों ऐसी वृद्धि पहले कभी देखी नहीं गयी। लेकिन इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें हल्के विनियमन और बहुत सरल शासन संरचना की आवश्यकता होगी। ■